# 'चुनाव परिणाम आने के 48 घंटे के भीतर प्र.मंत्री का चयन कर लेगा इंडिया गठबंधन'

## कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि, इस लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन स्पष्ट एवं निर्णायक जनादेश हासिल करेगा

नई दिल्ली, 30 मई। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने गुरुवार को कहा कि, इस लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन स्पष्ट एवं निर्णायक जनादेश हासिल करेगा और नतीजों के 48 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री का चयन कर लिया जाएगा। लोकसभा चुनाव के सातवें एवं अंतिम चरण के मतदान से पहले, प्रचार के आखिरी दिन साक्षात्कार में रमेश ने यह भी कहा कि विपक्षी गठबंधन में जिस पार्टी को सबसे अधिक सीट मिलेंगी, वही पार्टी अगली सरकार के नेतृत्व के लिए स्वाभाविक दावेदार होगी। उनका यह भी कहना था कि इंडिया जनबंधन के घटक दलों को जनादेश मिलने के बाद नैशनल डैमोक्रैटिक अलायंस (एन.डी.ए.) के कुछ घटक भी इस गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, हालांकि कांग्रेस आलाकमान को यह तय करना होगा कि उन्हें गठबंधन में शामिल किया जाए या नहीं। बता दें कि सातवें और आखिरी फेज की वोटिंग एक जून को होनी है, जबकि चार जून को नतीजों का ऐलान होगा।

■ **जयराम रमेश ने इस बात की ओर भी इशारा करते हुये कहा कि, जब इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलेगा तो एन.डी.ए. के कई घटक दल भी हमारे साथ आ सकते हैं।**

रमेश ने कहा कि, इंडिया गठबंधन स्थिर, पारदर्शी और जिम्मेदार सरकार देने को प्रतिबद्ध है। यह पूछे जाने पर कि, क्या चुनाव के बाद जनता (यूनाइटेड) के अध्यक्ष नीतीश कुमार और तेलुगू देसम पार्टी (तेदेपा) के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू जैसे भाजपा के सहयोगियों के लिए इंडिया गठबंधन के दरवाजे खुले रहेंगे, कांग्रेस नेता ने कहा, नीतीश कुमार पलटी के उस्ताद हैं। चंद्रबाबू नायडू 2019 में कांग्रेस के साथ थे। मैं बस इतना ही कहूंगा कि जब इंडिया जनबंधन के घटक दलों को जनादेश मिलेगा, तो इंडिया में राजग के कुछ घटक भी शामिल हो सकते हैं।

इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया, कांग्रेस आलाकमान खरगे, सोनिया और राहुल को फैसला करना होगा। उन्होंने कहा, इंडिया गठबंधन और एनडीए (राजग) में सिर्फ दो शब्दों का फर्क है। इंडिया से दो आई निकाल देने पर एनडीए बचेगा। इन दो आई का मतलब इंसानियत और ईमानदारी है। जिन पार्टियों में इंसानियत और ईमानदारी है वो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि लोगों से जनादेश मिलने के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार अधिनायकवादी नहीं, बल्कि शासनवादी होगी। लोकसभा चुनाव के छह चरणों के मतदान के बाद जमीनी स्थिति से जुड़े सवाल पर रमेश ने कहा कि इस चुनाव में भाजपा के पक्ष में कोई लहर नहीं, सिर्फ निवर्तमान प्रधानमंत्री का जहर रहा है।

उनके मुताबिक 20 साल बाद इतिहास फिर दोहराया जाएगा और विपक्षी गठबंधन को स्पष्ट एवं निर्णायक जनादेश मिलेगा। रमेश ने कहा, मैं संख्या के बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हमें निर्णायक बहुमत मिलेगा। 272 स्पष्ट बहुमत का आंकड़ा है लेकिन यह निर्णायक नहीं है। जब मैं निर्णायक जनादेश कहता हूं, तो मेरा मतलब 272 सीट से काफी ऊपर की संख्या है।

रमेश ने दावा किया कि कांग्रेस राजस्थान, कर्नाटक और तेलंगाना में अच्छी बढ़त हासिल करेगी और महाराष्ट्र में फायदे की स्थिति में होगी। उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस को फायदा होगा और भाजपा 2019 की अपनी 62 सीट से आगे नहीं जा पाएगी।

# 'मुस्लिम समाज काशी और मथुरा की मस्जिदों पर से दावा छोड़ दे'

नई दिल्ली, 30 मई। भारतीय जनता पार्टी के फायरब्रांड नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि मुसलमानों को काशी के ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह पर दावा करना छोड़ देना चाहिए। इन जगहों को हिंदुओं के लिए छोड़ देना चाहिए। ऐसा करने से इस्लामोफोबिया खत्म हो जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि तथाकथित धर्मनिरपेक्ष बुद्धिजीवी इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे।

इंटरव्यू में सरमा ने कहा, यदि आप मथुरा में शाही ईदगाह बनाना जारी रखते हैं तो वहां जाने वाले हिंदू स्वाभाविक रूप से नाराज होंगे। उन्हें शाही ईदगाह को किसी अन्य स्थान पर ले जाना चाहिए। इसके बाद जब कोई हिंदू मथुरा आएगा तो वह मुस्लिम समुदाय के प्रति कृतज्ञता के साथ वापस अपने घर आएगा।

सरमा ने यह भी कहा कि मस्जिद को बलपूर्वक नहीं हटाया जा सकता है, बल्कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच परामर्श के माध्यम से ही संभव यह हो सकता है। असम के सीएम ने कहा, अब मोदीजी काशी कॉरिडोर का निर्माण कर रहे हैं। हर कोई वहां जाता है।

# विधि विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर पुनर्विचार से इन्कार

## हाई कोर्ट ने लॉ युनिवर्सिटी के कुलपति नियुक्त किए गए डॉ. देव स्वरूप की पुनर्विचार याचिका खारिज की

जयपुर, 30 मई (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने डॉ. भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर (वी.सी.) के तौर पर डॉ. देवस्वरूप की नियुक्ति रद्द करने के संबंध में दिए आदेश पर पुनर्विचार करने से इन्कार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने इस संबंध में दायर पुनर्विचार याचिका को निस्तारित कर दिया है। चीफ जस्टिस एम.एम. श्रीवास्तव और जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की पीठ ने यह आदेश देवस्वरूप की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

■ **हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव और जस्टिस विनोद भारवानी की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि, डॉ. भीमराव अंडेबकर लॉ युनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. देवस्वरूप ने याचिका दायर होने के बाद इस्तीफा दिया था।**

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि, उन्होंने याचिका दायर होने के बाद अपना इस्तीफा दिया था। इसके अलावा अदालत ने याचिका में यह बिंदु तय किया था कि, कानून की पृष्ठभूमि नहीं रखने वाले को विधि विश्वविद्यालय (वि.वि.) का कुलपति नियुक्त नहीं किया जा सकता। ऐसे में आदेश पर पुनर्विचार करने की जरूरत नहीं है। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया है कि, न्यायालय ने उस आदेश में उनकी शैक्षिणक उत्कृष्टता पर कोई टिप्पणी नहीं की है और अदालत की टिप्पणी उन्हें किसी अन्य विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त करने के आड़े नहीं आएगी।

रिव्यु याचिका में कहा गया कि, अदालत के आदेश देने से पूर्व ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में अदालत को उनकी नियुक्ति रद्द करने का आदेश देने की जरूरत ही नहीं थी। गौरतलब है कि, खंडपीठ ने प्रोफेसर के.बी. अग्रवाल की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए देवस्वरूप की विधि विश्वविद्यालय के कुलपति के तौर पर की गई नियुक्ति को रद्द कर दिया था। अदालत ने कहा था कि, विधि विश्वविद्यालय के कुलपति को विधि शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव रखने वाला होना चाहिए। यह एकल विषय का विश्वविद्यालय है, ऐसे में अन्य एकल विषय के वि.वि. की तरह विधि वि.वि. के कुलपति को कानून शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव रखने वाला होना चाहिए।

# 72 दिनों में प्र.मंत्री मोदी ने 200 से ज्यादा रैलियां व 80 इंटरव्यू किये

## प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव आचार संहिता लागू होने के पहले से ही देश भर के लगभग सभी राज्यों के मैराथन दौरे कर रहे थे

नई दिल्ली, 30 मई। इस बार का लोकसभा चुनाव सात चरणों में संपन्न हो रहा है और चुनाव का नतीजा 4 जून को घोषित होगा। 16 मार्च को चुनाव आयोग की तरफ से लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई थी। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव आचार संहिता लागू होने के पहले से ही देश भर के लगभग सभी राज्यों का मैराथन दौरा कर रहे थे। लेकिन, चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ देश के दक्षिण छोर से शुरू हुआ उनका प्रचार अभियान उत्तर में स्थित पंजाब के होशियारपुर में आकर समाप्त हुआ। जहां पीएम मोदी ने गुरुवार को एक चुनावी रैली को संबोधित किया।

इस चुनाव में पार्टी के पक्ष में पीएम मोदी की मेहनत साफ नजर आई। विपक्ष के फायर ब्रांड नेताओं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल जैसे नेता एक तरफ और पूरे चुनाव प्रचार अभियान के दौरान नरेंद्र मोदी एक तरफ सबको अपनी ऊर्जा से टक्कर देते नजर आए। आंध्र प्रदेश के पालनाडु से चुनाव प्रचार की शुरुआत कर पीएम मोदी ने इस अभियान का समापन 30 मई को पंजाब के होशियारपुर में किया। यानी 75 दिन की इस अवधि में पीएम मोदी ने 180 रैलियां और रोड शो किए हैं।

पीएम मोदी की रैलियों के साथ उनके रोड शो और अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने का आंकड़ा देखें तो यह संख्या 206 है। इसके साथ ही उन्होंने इस दौरान 80 से ज्यादा मीडिया चैनलों, अखबारों, यूट्यूबरों, ऑनलाइन मीडिया माध्यमों को अपना साक्षात्कार दिया। मतलब औसतन हर दिन पीएम मोदी ने दो से ज्यादा रैलियां और रोड शो के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं, पीएम मोदी मार्च में चुनाव की घोषणा से पहले फरवरी और मार्च की 15 तारीख तक 15 रैलियां कर चुके थे।

पीएम मोदी ने सबसे ज्यादा 22 जनसभाएं और कुल 31 चुनावी कार्यक्रम यूपी में किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कर्नाटक में 11, तेलंगाना में 11, तमिलनाडु में 7, आंध्र प्रदेश में 5 और केरल में 3 रैलियां की हैं। पीएम मोदी ने बिहार में 20 चुनावी कार्यक्रम और महाराष्ट्र में 19 चुनावी कार्यक्रम के साथ पश्चिम बंगाल में 20 रैलियों को संबोधित किया। इसके साथ ही पीएम ने ओडिशा और मध्य प्रदेश में 10 चुनावी कार्यक्रम किए। वहीं, पीएम का फोकस झारखंड पर भी रहा।

# शशि थरुर का असिस्टैंट तस्करी करते गिरफ्तार

नई दिल्ली, 30 मई। केरल के तिरुवंतपुरम से कांग्रेस के सांसद शशि थरूर के असिस्टेंट को दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया है। ऐसी जानकारी है कि मामला सोने की तस्करी से जुड़ा हुआ है। उन पर तय सीमा से ज्यादा सोना रखने का आरोप है। वह दुबई से लौट रहे थे। मामले में जांच शुरू कर दी गई है। वहीं, इस पूरे में थरूर ने कहा है कि पकड़ा गया व्यक्ति उनके स्टाफ का पूर्व सदस्य था।

सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों ने मामले में जानकारी देते हुए कहा कि शशि थरूर के सहायक शिव कुमार को दुबई से लौटते हुए दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। दिल्ली कस्टम ने बुधवार 29 मई को दिल्ली हवाई अड्डे पर सोना तस्करी मामले में थरूर के पीए शिव कुमार समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया। शिव कुमार के कब्जे से

■ **सांसद शशि थरूर के असिस्टैंट को दुबई से लौटते वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया है। यह मामला सोने की तस्करी से जुड़ा हुआ है। असिस्टैंट पर तय सीमा से ज्यादा सोना रखने का आरोप है।**

कुल 500 ग्राम सोना बरामद किया गया।

सूत्रों के मुताबिक, अधिकारियों ने शिव कुमार से बड़ी मात्रा में सोना जब्त किया है और उनसे बरामद सोने से जुड़े दस्तावेज भी मांगे हैं। सोने की सच्चाई का पता लगाने के लिए जांच भी शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि सीमा शुल्क विभाग ने शिव कुमार के पास से करीब 30 लाख कीमत का सोना बरामद किया है। कथित सोने की तस्करी के मामले में दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़े गए शिव कुमार के बारे में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने प्रतिक्रिया दी है।

# कश्मीर में पर्यटकों की बस खाई में गिरी, 21 लोगों की मौत

## सभी यात्री हाथरस (यू.पी.) के थे, दुर्घटना में 60 से अधिक लोग घायल भी हुये हैं

अखनूर, 30 मई। उत्तर प्रदेश के हाथरस से यात्रियों को लेकर आ रही एक बस जम्मू के अखनूर के टांडा क्षेत्र में सड़क से उतरकर गहरी खाई में गिर गई, जिससे 21 लोगों की मौत हो गई और 60 से अधिक घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि यह दुर्घटना जिले के कालीधार इलाके में हुई। बस करीब 150 फीट नीचे खाई में लुढ़क गई थी।

जम्मू के जिला मजिस्ट्रेट ने एक्स पर बताया, ''उत्तर प्रदेश के हाथरस से यात्रियों को लेकर जा रही एक बस जम्मू के अखनूर के टांडा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। बचाव अभियान जारी है।'' वाहन तीर्थयात्रियों को शिव खोरी क्षेत्र ले जा रहा था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, ''जम्मू के पास अखनूर में हुई बस दुर्घटना में लोगों की मौत का समाचार मिला। इस क्षित को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं।''

■ **बस लुढ़ककर 150 फीट गहरी खाई में चली गई थी। घटना की खबर लगते ही तुरंत राहत अभियान शुरु किया गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।**

घायलों को अखनूर अस्पताल और जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक नरिंदर सिंह ने कहा, ''सीएसई अखनूर को पहले मृतकों की जानकारी मिल गई है। उन्होंने हमें बताया है कि वे लगभग 20-25 मरीज भेजेंगे, जिनमें से 16 मरीज पहले ही आ चुके हैं। यह एक पर्यटक वाहन था और ये लोग (यात्री) जम्मू के नहीं हैं, वे बाहर से हैं।''

## 'लू और तापघात ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

विभाग, ए.सी.एस. सार्वजनिक निर्माण विभाग, ए.सी.एस. जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, ए.सी.एस. वन विभाग, ए.सी.एस. बागवानी, ए.सी.एस. वायु प्रदूषण व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जयपुर के अध्यक्ष से जवाब देने के लिए कहा है।

अदालत ने कहा कि लू और शीतलहर से मौत के बचाव को लेकर 18 दिसंबर, 2015 को राज्यसभा में बिल पेश किया गया था। जिसमें लू और शीतलहर के संबंध में कई प्रावधान किए गए थे, लेकिन नौ साल बीतने के बाद भी अब तक यह विधेयक संसद से पारित होकर कानून नहीं बन सका है। अदालत ने कहा कि यह देखने में आया है कि कई एक्शन प्लान बनने के बाद भी उन्हें प्रभावी रूप से लागू नहीं किया गया। ऐसे में अब वक्त आ गया है कि ऐसे प्रावधानों को कानूनी अमली जामा पहनाया जा सके। अदालत ने कहा कि गत वर्ष दिल्ली आपदा प्रबंधन ने हीट वेव एक्शन प्लान बनाया था। जिसमें अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को भी ऐसा ही हीट वेव एक्शन प्लान बनाना चाहिए। वहीं आमजन की आवाजाही वाली सडकों पर पानी का छिड़काव किया जाए। इसके अलावा ट्रैफिक सिग्नलों पर छाया मुहैया कराई जाए। अदालत ने कहा कि आमजन, दैनिक वेतन भोगी, रिक्शा व ठेला चालकों को जरूरी होने पर ओ.आर.एस. के पैकेट दिए जाए, ताकि उन्हें हीट वेव स्ट्रोक से बचाया जा सके। राज्य सरकार सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर लू लगने से बीमार लोगों के इलाज के लिए सभी सुविधाएं मुहैया कराए। लोगों को भीषण गर्मी के बारे में विभिन्न माध्यमों के जरिए सचेत किया जाए।

अदालत ने इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ताओं से इस मामले में अपने विचार और विधिक जानकारी साझा करने के लिये कहा है। वरिष्ठ अधिवक्ताओं में आर.एन. माथुर, ए.के. शर्मा, कमलाकर शर्मा, आर.के. अग्रवाल, ए.के. भंडारी, एस.के. गुप्ता, अशोक मेहरा, आर.पी. सिंह व विवेक बाजवा शामिल हैं। अदालत में बार काउंसिल राजस्थान के अध्यक्ष रामप्रसाद सिंगरारिया व बार एसोसियेशन के अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा को भी अदालत का सहयोग करने को कहा है। अदालत ने महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद, अतिरिक्त महाधिवक्ता भरत व्यास और एडीशनल सोलिसिटर जनरल आर.डी. रस्तोगी को भी मामले में सहयोग के लिये कहा है।

## केजरीवाल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के मुख्यमंत्री को ई.डी. ने मनी लॉन्डरिंग स्कीम के मामले में भागीदार होने के आरोपों के चलते गिरफ्तार किया था, जो कि अब राज्य में रद्द शराब नीति से संबंधित है।

केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत मंजूर की थी। कोर्ट ने 29 मई को उनकी अंतरिम जमानत अवधि को बढ़ाने वाली याचिका पर सुनवाई से मना कर दिया था।

इस मामले पर सुविज्ञ अवस्थी, पार्टनर, पी.एस.एल. अधिवक्ता व सॉलिसिटर ने कहा कि "केजरीवाल के द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका के लम्बित रहने के चलते उनके नियमित जमानत मांगने के लिए आवेदन कर सकते है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 17 मई के आदेश में लिखा था। एक प्राकृतिक उपाय के रूप में, सबसे बेहतरीन तरीका अरविन्द केजरीवाल के लिए यह है कि वे शीघ्र नियमित जमानत के उपलब्ध सांविधिक उपायों का प्रयोग करते हुए आवेदन करें।''

## 'नये मकान मालिक से पुराने...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

खरीदा था। परंतु जब उन्होंने बिजली विभाग से बिजली कनेक्शन का आवेदन किया तो बिजली विभाग ने उनसे 5.50 लाख रुपये का बकाया देने को कहा जो पुराने मकान मालिक या उसके किरायेदार के बकाया थे। मामले की छानबीन करने पर पता चला कि 2014 में बिजली विभाग ने उसी मकान के ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले किरायेदार के पक्ष में एक व्यवसायिक बिजली कनेक्शन जारी किया था, परंतु दिसम्बर 2015 और जनवरी 2016 का बिजली का बिल उसके द्वारा नहीं भरा गया तो अगले माह उसका कनेक्शन हटा दिया गया। परंतु उसने एक चैक के साथ बिजली कनेक्शन और मीटर पुनः लगाने की गुहार की। जिसे विभाग ने उसी वर्ष जुलाई में पुनः लगा दिया।

विभाग की ओर से पैरवी कर रहे वकील विपिन गुप्ता ने कहा कि कनेक्शन लगाने के बाद सितम्बर 2018 तक बिजली के बिल जारी नही किये जा सके और किरायेदार द्वारा भुगतान नहीं किये गये बिलों की राशि 4.50 लाख रुपये हो गई।

उन्होंने आगे बताया कि किरायेदार द्वारा दिया गया पुराना चैक भी बाउंस हो गया, जिससे कुल बकाया 5.07 लाख रुपये का हो गया। उन्होंने कहा कि इस बकाया बिल को मकान मालिक को भरने के लिये 9 दिसम्बर 2022 को दिया गया। और मकान मालिक ने 5 अप्रेल 2023 को भुगतान करने के लिये एक चैक दिया जो भी बाउंस हो गया। बिजली विभाग के वकील का कहना था कि नियमानुसार हर माह निगम को बिजली कनेक्शन के लिये बिल जारी करना होता है और नहीं दिये जाने पर प्रतिमाह 10 फीसदी ब्याज भी लगाया जाता है।

पर अदालत ने इस तथ्य पर हैरानी जताई कि बिजली विभाग ने मूल किरायेदार का बिजली कनेक्शन तो जारी कर दिया पर यह भी नहीं देखा कि उसका चैक बैंक द्वारा स्वीकार किया भी जायेगा कि नहीं। अदालत ने इस पर आशंका जताई कि विभाग ने दो साल तक एक भी बिल जारी नहीं किया और अदालत ने कहा कि इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि विभाग ने दोषी पुराने किरायेदार के पक्ष में इतनी उदारता क्यों बरती। अदालत ने यह भी कहा कि जब 2023 में पुराने मकान मालिक का भी चैक बाउंस हो गया था तो उन्होंने उस पर कार्यवाही क्यों नहीं की और अपनी पत्रावली में बिजली कनेक्शन का 'अकाउंट क्लोज़्ड' क्यों दर्शाया। अदालत ने कहा कि इन सभी तथ्यों से निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं।

अदालत ने याचिकाकर्ता की गुहार कि उन्हें इतनी अधिक गर्मी के मौसम में बड़ी तकलीफ उठानी पड़ रही है, को स्वीकारा और कहा कि विद्युत वितरण निगम को अस्थाई कनेक्शन जारी करने के निर्देश दिये। अब इस मामले की सुनवाई 5 जुलाई को होगी।

## भाजपा के शुभेन्दु अधिकारी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आपराधिक आरोप लगा कर, केस दर्ज कर लिया गया है। भाजपा के झरग्राम चुनाव क्षेत्र के प्रत्याशी के खिलाफ, राज्य पुलिस ने गैर जमानती आरोप लगा दिए हैं।

विडम्बना है कि, आदिवासी प्रत्याशी प्रणत टुडू पर बदमाशों ने हमला बोला था और पथराव के दौरान सिर पर पत्थर लगने से वे जख्मी हो गए।

उनके निजी सुरक्षा गार्डस, जो कि केन्द्रीय बल के सदस्य हैं, के ऊपर भी हमला हुआ था और उनमें से एक के सिर पर चोट लगने से खून बहने लगा था।

प्रणत टुडू, जो कि पेशे से एक डॉक्टर हैं, के ऊपर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न और अन्य अपराधों के आरोप लगाए गए हैं, जब टेलीविजन पर उनको अपने सुरक्षाकर्मियों के साथ अपने चुनाव क्षेत्र से जान बचाकर भागते हुए देखा गया। इस प्रत्याशी पर गैर जमानती आरोप लगाए गए हैं और पुलिस उनको कस्टडी में लेने का प्रयास कर रही है।

■ **एक आदिवासी उम्मीदवार पर यौन शोषण का आरोप लगाया गया है, जबकि टी.वी. पर उसे अपने सुरक्षाकर्मियों के साथ जान बचाकर भागते हुए दिखाया जा रहा है, तृणमूल के बाहुबलियों के आक्रमण से बचाव के लिये।**

पुलिस कार्यवाही का यह एक मामला है जबकि, शिकायतों के ज्यादातर मामलों में पुलिस पर कोई कार्यवाही नहीं करने का आरोप लगता रहा है।

चुनावों के छठे चरण के एक दिन पहले, एक भाजपा कार्यकर्ता की मां पर हुए जघन्य हमले में, उस महिला के मरने के बाद भी अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। महिला पर रात में हुए हमले में, उसके सिर और शरीर पर इतनी चोटें आई थीं कि, उसकी पहचान तक नहीं हो पाई थी।

शेख शाहजहां के मामले में, एनफोर्समैंट डायरैक्टरेट (ई.डी.) की टीम पर, आरोपी ने हमले करवाये थे लेकिन, उसे एक महीने तक गिरफ्तार नहीं किया था, जबकि, सबको पता था कि, वह कहां पर है। मुख्यमंत्री, ममता बनर्जी ने उसको चरित्र प्रमाण पत्र भी दे दिया, यह कहते हुए कि शाहजहां के खिलाफ षड़यंत्र रचा गया है।

और कई मामलों में भाजपा नेताओं को चुनावों से पहले गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें अब तक नहीं छोड़ा गया है।

## बेंगलुरू जी.पी.ओ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अफवाह है कि कांग्रेस की चुनाव गारंटी अनुसार योग्य वर्गों की महिलाओं को प्रति माह 8500 रू. मिलेंगे।

जी.पी.ओ. पर महिलाओं की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि खुले में काउन्टर लगाने पड़े। जी.पी.ओ. के अधिकारियों ने कहा कि, अफवाह थी कि उनके खाते में पैसा आएगा इसलिए महिलाओं की भीड़ खाता खुलवाने के लिए उमड़ पड़ी है। महिलाओं को बताया गया कि, यह सिर्फ अफवाह है कि, जो शायद स्थानीय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने फैलाई है। उसके बाद भी महिलाएं इस गंभीरता से ले रही हैं। इसका कारण है कि, कर्नाटक की महिलाओं का अनुभव जो राज्य की सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर रही है।

कांग्रेस सरकार द्वारा मुफ्त यात्रा व अन्य मुफ्त सुविधाएं पाने के बाद महिलाओं को यकीन है कि कुछ ही महीनों में उन्हें सरकार से 8500 रू. मिलने लगेंगे। गौरतलब है कि, इस चुनाव में कर्नाटक में पुरूषों की तुलना में महिलाओं ने ज्यादा वोट डाले। कांग्रेस इसे शक्ति योजना की सफलता बता रही है और कह रही है कि महिलाओं ने इस प्रकार कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद दिया।

## धौलपुर के राजीविका...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगी।

बैठक में अभय कुमार ने राजीविका के पंचसूत्रों - साप्ताहिक बैठक, साप्ताहिक बचत, आंतरिक उधार, ऋण का भुगतान और रिकॉर्ड मेंटेनेंस के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि, राजीविका का प्रदेश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने महिलाओं की आजीविका में वृद्धि के लिए पंचरत्न मिशन के माध्यम से राजीविका द्वारा बनाए गए उत्पादों को बाज़ार तक पहुंचने पर जोर दिया। उन्होंने प्रदेश की महिलाओं को कृषि तकनीक में उन्नत और कृषि में अग्रसर बताया।

उन्होंने अफ्रीका और प्रदेश की वनस्पति में समानता के बारे में बताते हुए प्रतिनिधियों से कृषि और जल संरक्षण पर भी चर्चा की। उन्होंने राज्य में प्रचलित मोटे अनाज को अफ्रीकी देशों के वातावरण के अनुकूल बताते हुए मोटे अनाज को अफ्रीका में उगाने का सुझाव दिया।

बैठक के दौरान, राजीविका द्वारा प्रशिक्षित अफ्रीकी प्रतिनिधियों को राजीविका द्वारा किये जा रहे नवाचारों एवं कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इसके साथ ही, राज्य में स्वायत्त ग्रामीण समूहों से जुड़ी महिलाओं द्वारा नीम के बीज की खाद, औद्योगिक उत्पादन और मिलेट उत्पादों के बारे में जानकारी प्रतिनिधियों के साथ साझा की गई।

बैठक में, राज्य में कृषि संबंधित क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान पर भी चर्चा की गई।

इसके अलावा राजस्थान में नर्मदा नहर के माध्यम से जालोर एवं बाड़मेर जिलों में हो रही सिंचाई की प्रक्रिया के बारे में भी प्रेजेंटेशन एवं वीडियो के माध्यम से जानकारी दी गयी। राजीविका महिला समूह के लिए कार्य कर रही श्वेता कुमारी राठौड़ एवं संजय ने भी अफ्रीका के प्रतिनिधियों से विचार साझा किये।

# मनमोहन सिंह ने तीन पेज का खुला ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

थोप दी है। भाजपा देशभक्ति, शौर्य और सेवा का मूल्य मात्र 4 साल हैं।''

पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर शनिवार को मतदान होना है। हालांकि कांग्रेस का देश भर में आप से गठबंधन है पर यहां दोनों दल अलग-अलग चुनाव लड़ रहे हैं।

डॉ. सिंह ने कहा कि पंजाब के लोग शौर्य भावना से भरे होते है। इस समय इस महान देश को बचाने के लिए पंजाबियों के लिए अदम्य साहस और लोकतांत्रिक मूल्यों में अगाध विश्वास, सबको साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति और भाईचारे की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा, पंजाब और पंजाबी योद्धा हैं पर भाजपा सरकार ने पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

डॉ. मनमोहन सिंह ने मोदी पर निशाना साधा कि उन्होंने सार्वजनिक भाषण की मर्यादा आहत की है। अब से पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने इतने नफरती असंसदीय व असभ्य शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया और विपक्ष तथा समाज के खास वर्ग के लिए ऐसे अपशब्द नहीं कहे हैं।

डॉ. मनमोहन सिंह जो कि भारतीय आधुनिक अर्थव्यवस्था के प्रमुख रचियता में से एक हैं, उन्होंने 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था। उन्होंने यू.पी.ए. और एन.डी.ए. कार्यकालों का सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक मुद्दों पर तुलनात्मक विश्लेषण किया।

उन्होंने कहा, नोटबंदी जैसी विनाशकारी नीति थोपना, त्रुटिपूर्ण जी.एस.टी. सिस्टम लागू करना और कोविड महामारी के कुप्रबंधन से देश के लोगों की दशा बहुत दयनीय हो गई और 6 से 7 प्रतिशत जी.डी.पी. ग्रोथ जो सामान्य मानदंडों से बहुत कम है को अब सामान्य मान लिया गया है।

पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा, "भाजपा सरकार के शासन में औसत ग्रॉस डॉमैस्टिक प्रोडक्शन (जी.डी.पी.) वृद्धि दर गिरकर छः प्रतिशत पर आ गई जबकि कांग्रेस यू.पी.ए. के शासनकाल में यह लगभग आठ प्रतिशत के करीब थी (न्यू सीरीज)। अभूतपूर्व बेरोज़गारी व बेलगाम महंगाई ने देश में असमानता की खाई बहुत बढ़ा दी है, जो कि अब पिछले 100 वर्षों के उच्चतम स्तर है।''

विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2010 में यू.पी.ए. सरकार के कार्यकाल में देश की जी.डी.पी. वृद्धि दर उच्चतम 8.5 प्रतिशत तक पहुंच गई थी और (वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान) वर्ष 2008 में गिरकर न्यूनतम स्तर 3.1 प्रतिशत पर आ गई थी 10 वर्षों में यह (वर्ष 2021) में बढ़कर उच्चतम स्तर 9.1 प्रतिशत पर पहुंच गई थी और वैश्विक महामारी के दौरान यह गिरकर -5.8 प्रतिशत पर रह गई थी।

संयोगवश, केन्द्रीय बैंक द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी करने के कुछ घंटे बाद कांग्रेस ने डॉ. सिंह के पत्र को एक्स पर साझा किया जिसमें वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) वृद्धि दर सात प्रतिशत रहने की भविष्यवाणी की गई है।

पूर्व अर्थशास्त्री डॉ. सिंह ने कहा कि यू.पी.ए. सरकार ने चुनौतियों के बावजूद हमारे आमजन की क्रय शक्ति में वृद्धि की थी, जबकि भाजपा के कुशासन का परिणाम यह रहा कि घरेलू बचत में भारी कमी हुई है जो कि पिछले 47 वर्षों में सबसे न्यूनतम है, वित्त वर्ष 2022-23 में शुद्ध घरेलू वित्तीय बचत पांच वर्षों के न्यूनतम स्तर 14.2 ट्रिलियन पर आ गई जो कि कुल जी.डी.पी. का 5.3 प्रतिशत मात्र है।

वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की मार्च में रिपोर्ट जारी होने के बाद इस विषय पर उनकी यह चेतावनी आई है, इसमें कहा गया है कि भारतीय अमीर लोगों के पास आज राष्ट्र की आय का सबसे बड़ा हिस्सा है जो कि पिछले 100 वर्षों में सर्वाधिक है।

पूर्व प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में "सुधार-समायोजन" को भी रेखांकित किया जो पांच युवा न्याय स्तंभ के नाम से हैं- उनकी पार्टी के चुनाव घोषणा में युवाओं में व्याप्त बेरोज़गारी के संदर्भ मे है।'' 30 लाख सरकारी (रोजगार) शाली पद एवं अनगिनत पेपर लीक होने की घटनाओं के कारण युवाओं के भविष्य पर खतरे के काले बादल मंडरा रहे है।''

डॉ. सिंह ने अपने पत्र में यह भी कहा कि "हमने वादा किया है कि जॉब कलैण्डर निर्धारित करके उसके अनुसार एक व्यवस्थित तरीके से 30 लाख रिक्त पद भरे जाएंगे। इनमें से आधे पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। और पेपर लीक मामलों से निपटने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे।''

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादकः- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालयः-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालयः-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालयः-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालयः-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालयः एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908